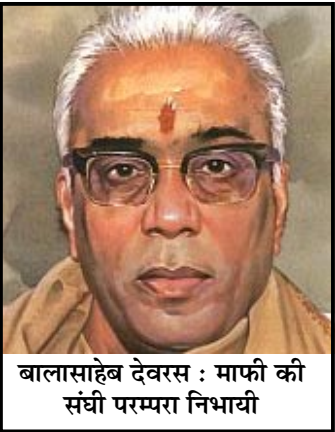


देवरस ने आपातकाल में पत्र लिख कर माफी मांगी थी



बालासाहेब देवरस : माफी की संधी परम्परा निभायी

खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व प्रमुख टीवी राजेश्वर सिक्किम और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। उनकी पुस्तक है "करुसियल इयर्स"। 2015 में इंडिया टुडे टीवी के कर्ण थापर शो में उन्होंने बताया था कि संघप्रमुख बालासाहेब देवरस ने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखकर माफी मांगी थी और बीससूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन का वायदा किया था। राजेश्वर ने यह भी कहा है कि इंदिरा गांधी शुरु में आपातकाल लागू होने के छह महीने बाद ही इसे हटाने का मन बना रही थीं, लेकिन अकूत शक्ति का आनंद ले रहे संजय गांधी इसके खिलाफ थे। संघ के लोग संजय गांधी के ही समर्थक थे।

संघ को लेकर तपन बसु, प्रदीप दत्ता, सुमित सरकार, तनिका सरकार द्वारा लिखी गयी चर्चित किताब 'खाकी शॉर्ट्स एण्ड सैफन फ्लेगज' भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको इस दौर की वो कुछ अनसुनी बातें बताने का काम कर सकती है। इस पुस्तक में संघ की आपातकाल के दौरान कार्यप्रणाली पर लोगों के सवाल का जवाब देने का कार्य किया है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि संघ इस दौरान इंदिरा की तारीफ क्यों कर रहा था और इंदिरा और संघ के सरसंघचालक के बीच में किस तरह का समझौता हुआ था। जेल में बंद संघवालों से क्या वचनपत्र भ्रवाएं गए और संघ से पाबन्दी हटवाने के लिए विनोबा भावे की मदद से संजय से मुलाकात के प्रयास भी शामिल हैं। संघ पर इस दौर में लगी पाबन्दी को अलग तरीके से समझने के लिए यह एक उपयुक्त पुस्तक है।

ग्वालियर जेल में आपातकाल के समय 18 महीने जेल रहे कम्युनिस्ट नेता बादल सरोज बताते हैं कि पहले 15 दिन में माफीनामों के दो कनस्तर भर गए थे, तभी बंद किये गए 375 लोगों में से आपातकाल समाप्त होते होते महज 50 ही लोग जेल में रह गए थे, माफी लिखकर जेल से बाहर आये लोग किस विचारधारा के थे? यह ग्वालियर में सभी जानते हैं।

राजद के सांसद रघुवंश प्रसाद ने लोकसभा में दावा किया था कि 'आपातकाल' में भाजपा और संघ के नेताओं ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से माफी मांगी थी। ताकि जेल से उन्हें मुक्ति मिले। उन्होंने आरोप लगाया था कि अटलबिहारी वाजपेयी ने पत्र लिखकर खुद इंदिरा गांधी से माफी मांगी थी। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रमुख बालासाहेब देवरस ने भी इंदिरा गांधी को माफीनुमा पत्र लिखा था। उन्होंने इसके लिए विनोबा भावे से सिफारिश कराई थी। इंदिरा गांधी को यह वायदा किया गया था कि संघ के कार्यकर्ता रिहा होने के बाद इंदिरा सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों में पूरा सहयोग करेंगे।

आपातकाल के दौरान एक लोकप्रिय नारा था "संजय, विद्या, बंसीलाल; आपातकाल के तीन दलाल"। इनमें से विद्याचरण शुक्ल ने भारतीय जनता पार्टी के टिकिट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, जो आपातकाल की प्रबल समर्थक रहीं, वे बरसों पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और भाजपा की टिकिट पर चुनाव लड़ती हैं। वे वर्तमान में मंत्री भी हैं। बंसीलाल आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के सर्वाधिक नजदीकी राजनेता समझे जाते थे। बाद में उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाई। बंसीलाल ने भी शायद कभी भी आपातकाल की निंदा नहीं की।

अचानक 41 साल बाद आपातकाल की ऐसी याद शक पैदा करती है कि "विकास" की मौत के बाद और पुराने गड़े मुद्दे से शायद 2019 की कूद लगायी जा सके?

हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के साथ काम कर चुके वाल्टर के एंडरसन और संघ से नजदीकी रखनेवाले श्रीधर डामले, जो कि संघ पर नये सिरे से एक किताब लिख रहे हैं, उनका दावा कुछ अलग है - इंदिरा गांधी से माफी मांगना एक रणनीति का हिस्सा था। यहां तक कि अटलबिहारी वाजपेयी को भी इंदिरा से माफी मांगने को कहा गया था। डामले ने यह भी बताया कि वाजपेयी जी ने मुझे बताया था कि मैं बिना इजाजत कुछ नहीं कर रहा।

एकनाथ रानाडे को आपातकाल के दौरान विवेकानंद मेमोरियल की स्थापना के लिए कन्याकुमारी भेजा गया था। वह छह साल तक सरकारीवाह रहे, लेकिन कन्याकुमारी जाने के बाद वह संघ में नहीं लौटे। यही विवेकानंद संस्था केजरीवाल सहित कई लोगों को उभार चुकी है। ???

- पंकज चतुर्वेदी

खबर (दार) झरोखा

विकास नारायण राय

एक न एक दिन हर फ़ासीवादी तानाशाह अपने साथे से डरेगा!

एमएचए यानी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर तमाम राज्यों को भेजे गए ताजातरीन निर्देशों को मीडिया में बाकायदा प्रचारित किया जा रहा है। पहली नजर में चौंकाने वाला लगता है कि अब मोदी के मंत्री और अफसर भी एसपीजी के सुरक्षा फिल्टर से गुजरकर ही उनसे मिल सकेंगे। अन्यथा आजमाये ढर्रे पर चल रही प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सुरक्षा कवायद में नया क्या हुआ है, विशेषज्ञों को यह देखना होगा।

यहाँ एमएचए का मतलब केंद्र सरकार की मुख्य इंटरलिजेंस एजेंसी आईबी यानी इंटरलिजेंस ब्यूरो से हुआ। माना जा सकता है कि आईबी ने अपने इस बेहद संवेदनशील एवं बाध्यकारी परामर्श को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संज्ञान में भी जरूर लाया होगा। शायद, इसकी तात्कालिकता को देखते हुए, एमएचए को भी भेजने से पहले। उनके लिए ऐसा करना ही स्वाभाविक होगा क्योंकि डोभाल स्वयं आईबी प्रमुख रह चुके हैं और फिलहाल मोदी के गिने-चुने विश्वासपात्रों में एक हैं।

हालाँकि, प्रधानमंत्री सुरक्षा के नजरिये से ऐसे निर्देश बेहद गोपनीय रखे जाने चाहिए थे, और सरकार के चाहे जिस स्तर पर भी इन्हें प्रचारित करने का निर्णय लिया गया हो उसके पास मोदी की सुरक्षा से इस हद तक प्रत्यक्ष समझौता करने की सुनियोजित वजह होनी चाहिए।

उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे को सत्ता राजनीति के घेरे में न घसीट लिया गया हो। यानी, राजनीतिक अविश्वास से घिरते माहौल में खतरा तो इस बात का है कि मोदी के अन्तरंग और विश्वस्त कथनों को कोई 'अपना' ही रिकॉर्ड न कर फायदा उठा ले, और हाँवा प्रचारित किया जा रहा हो प्रधानमंत्री सुरक्षा का, ताकि हर आम ही नहीं, खास से खास भी अपनी तलाशी होने पर चूँ करने लायक न रह जाए।

हाल में, नक्सल-दलित आतंकी गठजोड़ के माध्यम से मोदी को राजीव गाँधी का अंजाम देने वाली चिट्ठी बरामद करने के महाराष्ट्र पुलिस के दावों पर बेशक सवाल खड़े किये गए हैं। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री होते, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को विश्वसनीयता देने के लिए, सुरक्षा के नाम पर फर्जी पुलिस मुठभेड़ों के आरोपों का अध्याय भी अभी तक बंद नहीं हुआ हो। यही नहीं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो मौजूदा 'मोदी खतरे में' प्रसंग को उसी श्रंखला की ही कड़ी मानना चाहेंगे।

दूसरी तरफ, स्वतंत्र भारत में महात्मा गाँधी, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी और बंजरात सिंह की हत्याओं के रूप में पर्याप्त उदाहरण हमारे सामने हैं कि खतरा किसी अहानिकर और अनपेक्षित लगते रूप में भी प्रकट हो सकता है। निःसंदेह, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा कोई भी व्यक्ति हर समय शारीरिक हमले के निशाने पर रहेगा ही, और एसपीजी (विशेष सुरक्षा दल) का काम ही है कि संभावित खतरों से प्रधानमंत्री को दूर रखे।

मंत्रियों और अफसरों से मोदी को सीधे खतरा न भी हो लेकिन उन्हें अनजाने में खतरे का माध्यम बनाया जाना नामुमकिन भी नहीं। हालाँकि, इस विषय के अधिक विस्तार में जाना उचित नहीं होगा लेकिन यह कहा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी को राजनीतिक और सुरक्षा जरूरतों को संतुलित करने रहना पड़ सकता है। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गाँधी शुरुआत में सुरक्षा के प्रति पूरे बेपरवाह रहे थे जबकि नरसिंह राव जैसा सुरक्षा मानकों को मानने वाला कॉपी कैट प्रधानमंत्री शायद ही मिले।

तो भी, मोदी को शारीरिक हानि पहुँचाने को लेकर सरकारी इंटरलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी परस्पर क्या जानकारी बाँट रही हैं और तदनुसार उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रोटोकॉल तय कर रही हैं, इसे सार्वजनिक करना पेशेवर नजरिये से आत्मघाती ही कहा जाएगा। यदि सचमुच खतरा है तो भविष्य में मोदी के रोड शो न करने की सूत में भी राजनीतिक सफाई देने के लिए इतना कहना काफी होता कि ऐसा एसपीजी की सलाह पर हो रहा है। एसपीजी एक्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, एसपीजी की सलाह सभी के लिए बाध्यकारी होगी।

क्या यहाँ कोई और पेंच है? मोदी खतरे में किनसे हैं? दरअसल, हर फासिस्ट तानाशाह के जीवन में एक दिन आता है जब उसकी छाया भी उसे भयभीत करने लगे तो आश्चर्य नहीं। इसी छब्बीस जून को मोदी ने 43 वर्ष पूर्व लगी इमरजेंसी को देश के लिए 'काला दिन' बताया था और अरुण जेटली ने इंदिरा की तुलना जर्मनी के फासिस्ट तानाशाह हिटलर से की थी।

लेकिन देश पर इमरजेंसी थोपने वाली इंदिरा गांधी को जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपने सुरक्षा घेरे से सिख कर्मियों को हटाये जाने का पता चला तो उन्होंने एक बहुधर्मी लोकतंत्र की भावना के अनुरूप उन्हें वापस बुला लिया। यह और बात है कि सुरक्षा के समुचित पूर्वापाय न किये जाने से सुरक्षाकर्मियों के ही हाथों उनकी हत्या हो गयी।

नरेंद्र मोदी, बहुमत से चुने प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली भारत की धार्मिक एवं जातिगत विविधता से कोसों दूर का सम्बन्ध रखने वालों के ही प्रतिनिधित्व की रही है। अब सुरक्षा के नाम पर वे अपनी पार्टी में पहले से सीमित लोकतंत्र को और संकुचित करने की ओर बढ़ रहे लगते हैं।

'शव' राज में तब्दील होती शिवराज सरकार, प्रदेश में हर रोज मर रहे 61 बच्चे

मात्र 4 महीने में 7,332 बच्चों की मौत, वजह जानकर दहल जाएगा आपका दिल भी।

भोपाल, जनज्वार विशेष। सरकार दावा करते नहीं अघाती कि कुपोषण की मार से देश दिनोंदिन मुक्त होते जा रहा है, कि मोदी जी की अगुवाई में देश नए-नए प्रतिमान गढ़ रहा है, कि भाजपा राज में बच्चों के स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है, मगर हकीकत इतनी भयावह है कि रोगटो खड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में हर रोज 0 से 5 साल की उम्र के 61 बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं, वजह जानकर आपका दिल न दहल जाए तो कहना।

यह उस राज्य की हकीकत है जहां लंबे समय से भाजपा का राज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सत्तासीन शिवराज सरकार की। यहां हर दिन 0 से 5 साल की उम्र के 61 बच्चे कुपोषण के चलते मौत के मुँह में समा रहे हैं। यह जानकारी खुद राज्य की महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने विधानसभा में उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी।

मध्य प्रदेश में हर दिन 0 से 5 साल की उम्र के 61 बच्चों की मौत भूख से हो रही है। हर वर्ष केवल 1 साल तक की ही उम्र के तकरीबन 6,024 बच्चे भूख से मरते हैं। वहीं एक से पांच वर्ष आयु के 1,308 बच्चों की

मौत भूख से होने का आंकड़ा सामने आया है। मात्र 4 महीने में 7,332 बच्चों की मौत का भयावह सच सामने आया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि राज्य में प्रतिदिन भूख से 5 साल तक के कितने बच्चों की मौत होती है? फरवरी 2018 से मई तक 120 दिनों में कुल कितने बच्चे कम वजन के पाए गए और उनमें से कितने की मौत हुई।

इसके जवाब में अर्चना चिटनीस ने जानकारी दी कि इस दौरान कम वजन के 1,183,985 बच्चे पाए गए, और अति कम वजन के 103,083 बच्चों का आंकड़ा सामने आया। बड़ी तादाद में बच्चों की मौत का कारण उन्होंने अनेक बीमारियां गिनाईं।

कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने मीडिया से यह भयावह सच्चाई साझा करते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण दूर करने के तमाम दावे करती आई है, मगर बच्चों को नहीं बचाया जा सका है, जो कि बहुत दुखद है। बीते 120 दिनों में 7,332 बच्चों की मौत से साफ होता है कि हर रोज राज्य में 61 बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं।"

महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 14 सितंबर, 2016 को समीक्षा बैठक में श्वेत-पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे, समिति का गठन भी कर दिया गया, मगर समीक्षा के बिंदुओं का निर्धारण आज तक नहीं हो पाया है और न ही श्वेत-पत्र के लिए समिति की बैठक ही हो पाई है।

खुदा की चिड़ियाँ

हरिशंकर परसाई

पुराने जमाने में एक बार ईथोपिया के राजा ने हाथियों की सेना लेकर मक्का पर हमला कर दिया। तब एक चमत्कार हुआ। आसमान पर चोंच में कंकड़ लेकर अनगिनत चिड़ियाँ छा गयीं। चिड़ियों ने हाथियों पर कंकड़ बरसाये तो हाथी भाग खड़े हुए। यह चमत्कार है। वैसे यह चमत्कार तब नहीं हुआ जब कुछ छापामारों ने काबा पर कब्जा कर लिया था। कोई चिड़िया आसमान में नहीं उड़ी-कोई कंकड़ नहीं गिरा। खुदा के इंसान का कोई ठिकाना नहीं। कभी अपने ही घर पर क्या करवा देता है, कभी हज को जा रहे मुल्ला की स्टेशन पर जेब कटवा देता है। कौन जानता है उसकी लीला को!



सन् 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा कराई गयी धनराशि में पचास प्रतिशत की बढ़त। बधाई काला धन! बधाई नरेन्द्र मोदी!